राज एक्सप्रेस, भोपाल
8 FEB 2010

'शिव' की बात में दम है

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार-बार कहते हैं कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ कराए जाने चाहिए। बात दमदार है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कहा है कि लोकसभा-विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ कराए जाने चाहिए। सुझाव बेशकीमती है, पर राजनीतिक हलकों में यह बहस के केंद्र में भी नहीं आ पाया, जबकि आना चाहिए। यह इसलिए, क्योंकि देश में हमेशा चुनावों का मौसम बना रहना कोई शान की बात नहीं है। पूरे वर्ष कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर के चुनाव होते ही रहते हैं, जिससे विकास-कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है। जनहित के अन्य कार्यों पर भी इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। दरअसल, जिस प्रशासन को, जिन अधिकारियों-कर्मचारियों को जनता की समस्याएं सुलझानी होती हैं या विकास-कार्यों को जमीन पर उतारना होता है, वे ही जब आए दिन चुनाव में उलझे रहेंगे, तब हमारे बुनियादी कार्यों पर बुरा प्रभाव तो पड़ेगा ही।

यह सही है कि चुनाव लोकतंत्र के महायज्ञ होते हैं, पर यह महायज्ञ रोज ही न होता रहे, इसके लिए कुछ उपाय तो करने ही होंगे। इसमें कोई कठिनाई नहीं है कि हम हर पांच साल बाद दो-तीन महीने की एक अवधि को चुनावी-अवधि घोषित कर दें, फिर सभी स्तरों के चुनाव उसी अवधि में करा लें। इसके बाद हमें पौने पांच साल का समय जन-समस्याओं के निराकरण और विकास कार्यों के लिए मिल जाएगा। जब हम अपने संविधान में डेढ़ सैकड़ा संशोधन कर चुके हैं, तो एक संशोधन यह भी हो सकता है कि लोकसभा-विधानसभाओं में पूर्ण-बहुमत के अभाव में सबसे बड़े दल को सरकार चलाने का मौका मिलना चाहिए। इससे मध्यावधि चुनावों से बचा जा सकता है। वहीं, उपचुनावों पर रोक लगाना भी वक्त की जरूरत है, चाहे रास्ता कोई भी निकालना पड़े। यह सब होगा तब, जब शिवराज के सुझाव पर राष्ट्रव्यापी बहस होगी, पर फिलहाल तो राजनीतिक हलकों में चुप्पी ही छाई हुई है।